RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 045
दि. 14.06.2025, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम ने अहमदाबाद हवाई हादसे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद यहां का दौरा किया। इस विमान दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी पूर्ण संवेदना व्यक्त करते हुए, श्री मोदी ने इस हादसे में घायल हुए लोगों से भेंट की, जिसमें एकमात्र जीवित बचे एक सज्जन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में पूरे देश के संपूर्ण भाव से उनके साथ होने का भी आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों का आकलन करने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की।

एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में श्री मोदी ने कहा:

"अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बाद घायल हुए लोगों से भेंट की, इनमें एकमात्र जीवित बचे सज्जन से मुलाकात भी शामिल है। उन्हें भरोसा दिलाया कि हम इस कठिन समय में उनके और उनके परिवारों के साथ हैं। पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।"

"अहमदाबाद हवाई अड्डे पर शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।"

संक्षिप्त समाचार

उपराष्ट्रपति 15 से 17 जून, 2025 तक पुडुचेरी का दौरा करेंगे

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 15 से 17 जून, 2025 तक पुडुचेरी की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 16 जून को उपराष्ट्रपति जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर) द्वारा 'राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थायित्व' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 17 जून को दौरे के समापन पर उपराष्ट्रपति और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका कल अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में निधन हो गया है था। श्री मोदी ने श्री रूपाणी के प्रतिष्ठित करियर पर प्रकाश डाला, जिसमें राजकोट नगर निगम में उनके कार्यकाल, राज्यसभा सांसद, गुजरात भाजपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी विभिन्न भूमिकाओं में उनके योगदान को याद किया गया।

एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट में, श्री मोदी ने लिखा: "श्री विजयभाई रूपाणी जी के परिवार से मिला।

यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल थे।

विजयभाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति दृढता से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने धीरे-धीरे पद्दोनति पाई, संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से सेवा की।"

सौंपी गई हर भूमिका में, उन्होंने खुद को प्रतिष्ठित किया, चाहे वो राजकोट नगर निगम में हो, राज्यसभा सांसद के रूप में हो, गुजरात भाजपा अध्यक्ष के रूप में हो या वो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हो।"

"विजयभाई और मैंने तब भी बड़े पैमाने पर काम किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात के विकास पथ को बढ़ाने के लिए कई उपाए किए, विशेष रूप से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने में। हमारे बीच हुई बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति।"

प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बातचीत की

पीएम मोदी ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्र में बदलती स्थिति के संबंध में बातचीत की। चर्चा के दौरान नेतन्याहू ने श्री मोदी को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया, जबकि प्रधानमंत्री ने स्थिति पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और वैश्विक शांति प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा: "इजराइल के पीएम @Netanhu से फोन आया। उन्होंने मुझे बदलती स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया।"

43 नदी सेतु, 28 आरओबी व 5 फ्लाईओवर के उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण में सफल रही योगी सरकार

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार नए प्रतिमान गढ़ रही है। सीएम योगी के विजन का असर है कि प्रदेश में मात्र एक साल में 76 सेतु परियोजनाओं का निर्माण उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए पूरा कर लिया गया है। लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उपलब्धि को हासिल किया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जिन 76 सेतु परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया उनमें 43 नदी सेतु, 28 आरओबी व 5 फ्लाईओवर शामिल हैं।

खास बात यह है कि यह उपलब्धियां केवल एक वर्ष की अवधि तक सीमित नहीं है। सीएम योगी के

अब तक के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्य प्रदेश की भविष्य की जरूरतों अनुसार उत्तम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 8 वर्षों में सीएम योगी के निर्देश व मार्गदर्शन में उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने कुल 471 सेतु परियोजनाओं के उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण में सफलता प्राप्त की है। इसमें 313 नदी सेतु, 143 आरओबी तथा 15 फ्लाइओवर शामिल हैं।

लोकनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड के टर्नओवर में भी सीएम योगी के अब तक के कार्यकाल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

एक ओर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां कुल टर्नओवर 1013.74 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 1360.34 करोड़ पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में भी वृद्धि दर्ज करते हुए टर्नओवर क्रमशः 1511.18 करोड़, 1936.92 करोड़ तथा 1959.33 करोड़ रहा।

अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना: विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाली विदेश मंत्रियों से बातचीत की

(जीएनएस)।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को पुष्टि की कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद, उन्होंने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ-साथ अपने कनाडाई और पुर्तगाली समकक्षों से भी संपर्क किया है। इस दुखद घटना में विमान में सवार 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली और एक कनाडाई शामिल थे। एयर इंडिया ने बताया कि दुर्घटना में 241 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक जीवित बचे व्यक्ति का वर्तमान में इलाज चल रहा है।

जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रभावित देशों को पूर्ण समर्थन की पेशकश की। गुरुवार को हुई दुर्घटना में कम से कम 265 लोगों की मौत हो गई, जो इसे हाल के भारतीय इतिहास

की सबसे गंभीर विमान दुर्घटनाओं में से एक बनाती है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेकऑफ के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया। हताहतों में जमीन पर मौजूद कई लोग भी शामिल थे।

यूरोप की एक आधिकारिक यात्रा पर, जयशंकर ने मार्सिले में फ्रांसीसी समकक्ष जीन-नोएल बारोट के साथ मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने घटना की दुखद प्रकृति को स्वीकार किया और यूके, पुर्तगाल और कनाडा के अधिकारियों के साथ चल रहे संचार पर प्रकाश डाला, क्योंकि उनके नागरिक पीड़ितों में शामिल थे। उन्होंने फ्रांसीसी सरकार की संवेदना और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और दुर्घटना की जांच के संबंध में आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने पर जोर दिया।

डेविड लैमी ने जयशंकर के संदेश को दोबारा पोस्ट किया, संवेदना व्यक्त करते हुए और इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत की सहायता के लिए यूके की तत्परता की पुष्टि की। जयशंकर ने विदेशी नेताओं और सरकारों को जीवन की हानि पर सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद भी दिया।

वैश्विक संवेदनाएं

गुरुवार दोपहर को अहमदाबाद हवाई अड्डे से प्रस्थान करने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होने पर विमान में 242 यात्री और चालक दल सवार थे। कई विश्व नेताओं ने त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस विनाशकारी घटना के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत भर में दूतावासों ने भी दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है।

गौतम गंभीर की मां को आया हार्ट अटैक, आईसीयू में हुई भर्ती, कोच ने छोड़ा भारतीय टीम का साथ!

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर फैमिली इमरजेंसी के कारण भारत लौट आए हैं। गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे को बीच में छोड़कर अचानक भारत आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम गंभीर की मां सीमा गंभीर को 11 जून को दिल का दौरा पड़ा था। फिलहाल उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर उनके साथ मौजूद हैं। गौतम गंभीर की भारतीय टीम को 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के लिए भी बहुत खास है क्योंकि यह उनका पहला बड़ा टेस्ट असाइनमेंट होगा।

12 जून 2025 को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट का मिल गया ब्लैक बॉक्स, अब खुलेगा प्लेन क्रैश का राज

(जीएनएस)।

अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर (AI171) विमान गुरुवार (12 जून 2025) को टेक-ऑफ करने के तीन मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ इसकी वजह का पता लगाने में विशेषज्ञों की टीम जांच में जुट चुकी है।

वहीं हादसे के एक दिन बाद जांच टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे की वजहों को समझने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कहां मिला ये ब्लैक बॉक्स और कैसे इतने बड़े हादसे में सुरक्षित बचा?

कहां मिला ये ब्लैक बॉक्स

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने शुक्रवार को पुष्टि की कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (डीएफडीआर), जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है, वो उसी इमारत की छत से बरामद किया गया है जहां एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

ब्लैक बॉक्स फ्लाइट में लगी एक छोटी डिवाइस होती है। इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है लेकिन पानी या मलबे के बीच असानी से नजर आने वाली ऑरेंज कलर का चमकीला उपकरण होता है। ब्लैक बॉक्स विमान की उड़ान के दौरान की सारी जानकारी अपने आप रिकॉर्ड करता है। बरामद किए गए डीएफडीआर यानी ब्लैक बॉक्स से फ्लाइट की दुर्घटना के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। विमानन मंत्री ने जताई ये उम्मीद

विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स पर लिखा, "एएआईबी द्वारा अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल से 28 घंटों के भीतर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) बरामद कर लिया गया है। यह जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे घटना की जांच में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।"

गौरतलब है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद- लंदन एयर इंडिया के बोइंग विमान में 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद एयर पोर्ट के रनवे से टेक-ऑफ करने के तीन मिनट बाद ही पास के रिहायशी इलाके में क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील हो गया था।

इस प्लेन में सवार केवल एक यात्री जिंदा बचा है जो भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक। बाकी 241 की हादसे में मौत हो गई है।

सना मकबूल को हुआ लिवर सिरोसिस, टूट गई हैं एक्ट्रेस, कहा- मैं मजबूत हूं, मेरे लिए दुआ करो

टीवी की फेमस एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इन दिनों काफी मुश्किलों से घिरी हुई हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने अस्पताल से अपनी एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया था। अब सना मकबूल ने खुद अपनी बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खबर है कि सना मकबूल को लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। ये बीमारी उन्हें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के कारण हुई है। इस खबर के सामने आते ही एक्ट्रेस के फैंस काफी चिंतित हो गए हैं। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सना मकबूल ने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है। सना ने कहा है- मैं कुछ समय से ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से जूझ रही हूं।

यूपी में 8 वीं तक के स्कूल अब 30 जून तक रहेंगे बंद, गर्मी को देखते हुए बढ़ाई गई छुट्टियां

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लू का असर इतना ज्यादा है कि अब छोटे बच्चों के लिए छुट्टियों की मियाद बढ़ा दी गई है। पहले जहां 15 जून तक छुट्टियां घोषित थीं, अब ये अवधि 30 जून तक कर दी गई है।

यह फैसला सिर्फ छात्रों के लिए लागू होगा। यानी कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब जून के अंत तक बंद रहेंगे। लेकिन शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को 16 जून से तय समय के अनुसार उपस्थित रहना होगा।

शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात छात्रों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरे हैं, इसलिए यह कदम एहतियातन उठाया गया है।

शिक्षकों पर ज़िम्मेदारी बरकरार

परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पहले 20 मई से 15 जून तक की गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थीं। लेकिन अब गर्म हवाओं और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए यह अवधि बढ़ा दी गई है।

छात्रों को अब 1 जुलाई से ही विद्यालय आने की अनुमति होगी। इस दौरान स्कूलों में कोई शैक्षणिक गतिविधि छात्रों के लिए संचालित नहीं की जाएगी। सिर्फ शिक्षकों को स्कूल आना होगा, जिससे बाकी प्रशासनिक कार्य पूरे किए जा सकें।

निजी स्कूलों को दी गई निर्णय की स्वतंत्रता

जहां सरकारी स्कूलों के लिए यह निर्णय अनिवार्य है, वहीं निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वह चाहें तो परिषद के निर्देश का पालन करें या फिर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छुट्टियों को लेकर निर्णय लें।

सम्पादकीय

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्यायपालिका पर जनता का भरोसा तभी कायम रह सकता है जब न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि होता हुआ भी दिखे और जस्टिस गवई की तरह अगर हर न्यायाधीश यह तय कर ले कि उनका काम सिर्प न्याय करना है, किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं, तब ही भारत की न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे ईमानदार और मजबूत संस्थाओं में शुमार हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर राजनीति की आंच से बचाव, जस्टिस गवई का साहसिक कदम भारत की न्यायपालिका में एक नई और ऐतिहासिक पहल की शुरूआत हुई है, जब देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामवृष्ण गवई ने यह ऐलान किया कि वे रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। इस साहसिक निर्णय ने सिर्प न्यायपालिका की गरिमा को नया सम्मान दिया है, बल्कि जनता के मन में भरोसे की उस डोर को भी मजबूत किया है जो पिछले वुछ समय से कई घटनाओं के चलते कमजोर होती जा रही थी। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यांम में उन्होंने कहा कि उनके वुछ अन्य साथी न्यायाधीशों ने भी यह संकल्प लिया है कि वे भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद या राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रखेंगे। चीफ जस्टिस गवई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं की ओर इशारा करता है, जिनमें वुछ रिटायर्ड जजों ने सरकारी पद स्वीकार किये हैं या राजनीति में साियं भागीदारी ली है। मसलन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया और हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद बन चुके हैं। जस्टिस गवई का कहना है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के बाद तुरंत कोई सरकारी पद या राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तो इससे जनता के बीच यह संदेश जाता है कि शायद उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पैसले किसी स्वार्थ या लालच के तहत लिये थे। इससे न्यायपालिका की साख पर आंच आती है और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। वे कहते हैं, ह्यह्यन्यायपालिका को केवल न्याय करना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वह पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदार है। "लोगों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।" भारत में न्यायपालिका को संविधान द्वारा स्वतंत्र और स्वायत्त घोषित किया गया है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद कोई जज राजनीतिक दल में शामिल होता है या किसी सरकारी संस्था में उच्च पद ग्रहण करता है, तो इस स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं। यह सवाल केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक खतरनाक परंपरा की शुरूआत हो सकती है, जिसमें न्यायिक पदों का राजनीतिक उपयोग होने लगे। जस्टिस गवई का यह रुख ऐसे समय में आया है जब देश में न्यायपालिका और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में चुनाव आयुत्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, लेकिन वेंद्र सरकार ने संसद से कानून पास कर इस व्यवस्था को बदल दिया और समिति से न्यायपालिका को बाहर कर दिया। इस घटनाव्रम ने फिर से न्यायपालिका की भूमिका और अधिकारों पर बहस को जन्म दे दिया। सिर्प राजनीतिक नियुक्तियों की बात नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाये हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी जांच की खबर सोशल मीडिया पर छाई रही, लेकिन वे अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं अशोका यूनिर्वसिटी के प्रोपेसर अली खान महमूदाबाद को भी एसआईटी जांच का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यह दोहरे मापदंड न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों को और हवा देते हैं। इन सबके बीच, जस्टिस गवई ने कॉलेजियम प्रणाली की भी आलोचना की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी हाल में खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, लेकिन कोई भी सुधार इस तरह नहीं होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाए।

नई दिल्ली में कल मिश्रित स्वरूप में 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' पर वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 आयोजित किया जाएगा

सम्मेलन में हजार से अधिक प्रतिभागियों के साथ दुनिया भर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय योग संस्थान और स्वास्थ्य समुदाय आभासी मा यम से जुड़ेंगे

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक के प्रभाव पर कल एक अध्ययन रिपोर्ट -"योग प्रभाव" जारी की जाएगी

(जीएनएस)। आयुष मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में 14 जून 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मिश्रित स्वरूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन ह्ययोग कनेक्टह्नआयोजित करेगा। वैश्विक सम्मेलन में भारत और विदेश से योग गुरू, नीति निमार्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, व्यापारिक दिग्गज, शोधकर्ता और वैश्विक तौर पर सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले विशिष्ट जन भाग लेंगे।

कार्यक्रम का समन्वय योग क्षेत्र के शीर्ष शोध निकाय, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) कर रहा है। योग कनेक्ट 2025 सम्मेलन मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय योग संस्थान और स्वास्थ्य समुदाय वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे साथ ही इसमें एक हजार से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। बहरीन, अमरीका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित चार से अधिक देशों के योग, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और कल्याण के क्षेत्रों के जाने-माने विशेषज्ञ सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी भागीदारी भारत के योग आंदोलन के वैश्विक महत्व को रेखांकित करती है।

शिखर सम्मेलन में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव संबंधी राष्ट्रव्यापी अध्ययन संबंधी ह्ययोग प्रभावह्नरिपोर्ट जारी की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहल की देश भर में पहुंच, प्रभावशीलता और परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाली यह रिपोर्ट शिक्षाविदों, शोधकताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होगी।

इसके अलावा, तीन महत्वपूर्ण ज्ञान कोष का अनावरण किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं:

योग का दशक भर में पड़ने वाले प्रभाव पर ई-बुक

योग अनुसंधान के विज्ञानमितीय; (साइंटोमेट्रिक) विश्लेषण पर रिपोर्ट

भारतीय वृक्ष वैभवमः देशी भारतीय वृक्षों के महत्व और उनकी प्रासंगिकता का उल्लेख करने वाली चित्रात्मक पुस्तिका

शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:

- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए योग
- सामान्य योग नियमों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रभाव आकलन
- योग-तकनीकः नवप्रवर्तकों की प्रस्तुति
- सभी के लिए योग दृष्टि
- योग और इसके अनुप्रयोग
- योग और जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं का स्वास्थ्य
- योग वाणिज्य और उद्योग

योग कनेक्ट सम्मेलन का मुख्य आकर्षण योग क्षेत्र के दिग्गजों की भागीदारी होगी जिनमें स्वामी बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, श्री एचआर नागेंद्र, भिक्खु संघसेना और श्री भारत भूषण भाग लेंगे।

'योग कनेक्ट' योग के भविष्य को आकार दे रहे लोगों को साथ लाने का एक अनूठा अवसर होगा। यह भारत के वैश्विक योग आंदोलन के दस वर्ष पूरा होने का प्रतीक है जो 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के साथ आरंभ हुआ था। यूनेस्को ने भी योग को विश्व के लिए भारत का उपहार माना है। इस तरह के आयोजनों से भारत का दुनिया के साथ स्वास्थ्य, संतुलन और एकता का संदेश साझा करना जारी है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और शेल इंडिया ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से हरित कौशल-केंद्रित ईवी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

इस साझेदारी के अंतर्गत चुनिंदा आईटीआई और एनएसटीआई में छात्रों को हरित कौशल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी

यह कार्यक्रम शेल के कार्यान्वयन साझेदार एडुनेट फाउंडेशन द्वारा 5 राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा; इसके माध्यम से हजारों छात्रों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा में उद्योग-तैयार कौशल प्रदान किए जाएंगे

भारत के हरित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के अनुरूप, यह पहल तेजी से विकसित हो रहे ऊर्जा क्षेत्र में प्रमाणन, नियोजन सहायता और हरित रोजगारों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी

प्रविष्टि तिथिः 13 खवठ 2025 11:10अट ु८ ढक्ह ॵ

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने शेल इंडिया के सहयोग से ग्रीन स्किल्स एवं इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों को ग्रीन एनर्जी एवं ई-मोबिलिटी में भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं से लैस करना है। इस पहल को शेल के प्रशिक्षण भागीदार एडुनेट फाउंडेशन द्वारा 12 जून 2025 को दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) एवं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में क्रियान्वित किया जाएगा।

डीजीटी-शेल इंडिया सहयोग के अंतर्गत चुनिंदा एनएसटीआई और आईटीआई में संरचित बहु-स्तरीय मॉडल के माध्यम से हरित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में, कार्यक्रम में 4 एनएसटीआई में 240 घंटे का उन्नत ईवी तकनीशियन पाठ्यक्रम, शेल समर्थित प्रयोगशालाओं से सुसज्जित 12 आईटीआई में 90 घंटे का रोजगारोन्मुख ईवी कौशल पाठ्यक्रम और भौतिक प्रयोगशालाओं के बिना आईटीआई में 50 घंटे का अतिरिक्त आधारभूत हरित कौशल मॉड्यूल शामिल है। शेल, एडुनेट फाउंडेशन और डीजीटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पाठ्यक्रम में ईवी सिस्टम, डायग्नोस्टिक्स, बैटरी तकनीक, डिजिटल उपकरण और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं। इस पहल में 250 से अधिक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), शेल और डीजीटी द्वारा सह-ब्रांडेड प्रमाणन और उद्योग की तत्परता बढ़ाने के लिए संरचित नियोजन सहायता भी शामिल है।

इस पहल का एक मुख्य आकर्षण चुनिंदा आईटीआई और एनएसटीआई के भीतर विशेष ईवी कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना है। इन प्रयोगशालाओं को उद्योग मानकों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रयोगशाला-आधारित शिक्षा के अलावा, कार्यक्रम सफल प्रतिभागियों को नियोजन सहायता और सह-ब्रांडेड प्रमाणपत्र भी प्रदान करता है, जिससे हरित ऊर्जा और ईवी क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।

भारत सरकार अपनी नेट-जीरो महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को अपनाने को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (एफएएमई) जैसी प्रमुख पहलों ने ईवी को अपनाने में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और लक्षित प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन राष्ट्रीय प्रयासों को पूरक बनाते हुए, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव को तेज करने, स्थानीय ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने और हरित रोजगारों का सृजन करने के लिए अपनी स्वयं की ईवी नीतियां पेश की हैं। ये विकास हरित ऊर्जा और ईवी क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को रेखांकित करते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में, डीजीटी छात्रों और प्रशिक्षकों को संगठित करके और राष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत इकोसिस्टम का समर्थन करके इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने इस पहल के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शेल इंडिया के साथ हमारा सहयोग कौशल को स्थिरता के साथ जोड़ने की सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और व्यापक जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय अनिवार्यताएं ही नहीं हैं, वे भारत के लिए नवाचार, प्रतिभा और उद्यम के माध्यम से नेतृत्व करने के लिए एक पीढ़ीगत अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल एक ऐसा कार्यबल बनाने के हमारे बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है जो न केवल रोजगार के लिए तैयार है, बल्कि जलवायु के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हम युवा भारतीयों को न केवल इसमें शामिल होने बल्कि वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए कौशल से लैस कर रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) की महानिदेशक श्रीमती त्रिशालजीत सेठी ने कहा कि शेल इंडिया के साथ यह साझेदारी हमारे आईटीआई और एनएसटीआई में अत्याधुनिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम लाने की दिशा में एक केंद्रित पहल है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकीकृत करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे छात्र वास्तविक दुनिया की मांग के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल संयुक्त प्रमाणन, प्रशिक्षक कौशल विकास और नियोजन सहायता के साथ, यह पहल ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र में हमारे युवाओं की रोजगार क्षमता को काफी मजबूत करेगी।

भारत में शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन और एशिया-पैसिफिक में शेल लुब्रिकेंट्स की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानसी मदन त्रिपाठी ने इस साझेदारी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शेल में, हमारा लक्ष्य भविष्य के रोजगार के अवसरों को सक्षम करके स्थानीय समुदायों का समर्थन करना है। युवाओं को हरित ऊर्जा कौशल से लैस करना कम कार्बन वाले भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीजीटी और एडुनेट फाउंडेशन के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से, हम छात्रों को हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में व्यावहारिक और भविष्य के लिए तैयार विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं। यह पहल युवाओं को एक उभरते ऊर्जा परिदृश्य में पनपने और भारत की शुद्ध-शून्य महत्वाकांक्षाओं में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है।

उन्होंने कहा कि डीजीटी और शेल इंडिया के बीच यह सहयोग भारत के युवाओं को भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था में करियर के लिए तैयार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। एक व्यापक पाठ्यक्रम, विशेष प्रयोगशालाओं और उद्योग समर्थन की पेशकश करके, यह पहल छात्रों को व्यावहारिक कौशल और प्रमाणपत्रों से लैस करेगी, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी और उन्हें एक स्थायी, नवाचार-संचालित भविष्य में नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगी।

भारत में क्यों खेला जाता है ईरानी कप, कैसे हुई थी शुरूआत

(जीएनएस)। ईरानी कप भारत में खेला जाने वाला एक भारतीय घरेलू टूनार्मेंट है। ईरानी कप नाम से कुछ फैंस इस टूनार्मेंट को ईरान से जोड़ते रहे हैं। लेकिन ईरानी कप का ईरान देश से कोई भी लेना देना नहीं है। ईरानी कप भारत में घरेलू खिलाड़ियों के बीच होने वाला एक पॉपुलर टूनार्मेंट है जो फैंस के बीच सुर्खियां बटोरती रही है। इस टूनार्मेंट में भारत के लिए नेशनल टीम में खेलने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा लेते रहे हैं।

घरेलू क्रिकेट का टूनार्मेंट है ईरानी कप

ईरानी कप भारत के घरेलू क्रिकेट का एक अहम और प्रतिष्ठित टूनार्मेंट है। यह एक फर्स्ट क्लास मैच होता है, जो हर साल रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम और शेष भारत की टीम के बीच खेला जाता है। शेष भारत की टीम में देश भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुना जाता है, जो उस साल रणजी ट्रॉफी नहीं जीत पाए होते हैं। इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है।

कब हुई थी ईरानी कप की शुरूआत

ईरानी कप की शुरूआत 1959-60 में हुई थी। इसे रणजी ट्रॉफी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। इस टूनार्मेंट का नाम स्वर्गीय जेड. आर. ईरानी के नाम पर रखा गया, जो 1928 से 1970 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े रहे। इस कप का पहला मुकाबला मार्च 1960 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में खेला गया था।

पहली बार किस टीम को मिली थी जीत

इस मैच में रणजी विजेता बॉम्बे (अब मुंबई) और शेष भारत की टीम आमने-सामने थीं। बॉम्बे की टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दर्ज की थी। ईरानी कप का मैच पांच दिनों तक चलता है और इसमें हर दिन न्यूनतम 90 ओवर गेंदबाजी करना जरूरी होता है। इसका मकसद है कि खेल में तेजी बनी रहे और दोनों टीमें जीत के लिए पूरा प्रयास करें।

मुंबई और शेष भारत में किसका पलड़ा रहा है भारी

यह मैच न केवल रणजी विजेता टीम के लिए एक परीक्षा होता है, बल्कि शेष भारत की टीम के लिए खुद को साबित करने का एक शानदार मौका होता है। अब तक मुंबई की टीम ने सबसे ज्यादा बार इस टूनार्मेंट में हिस्सा लिया है और 14 बार विजेता रही है। वहीं शेष भारत की टीम ने भी 30 बार यह कप जीता है। मुंबई की टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में साल 2024-25 का ईरानी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था।

इजराईली एयरस्ट्राइक में 78 मौतें, भड़के ईरान ने यूएस संग तोड़ी परमाणु वार्ता, हमले के बारे में 10 सवालों के जवाब

मध्य-पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां इजरायल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 78 लोगों की मौत और 329 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, इजरायल ने तेहरान सहित कई शहरों पर 5 चरणों में हवाई हमले किए, जिसमें 20 से ज्यादा वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए।

इन हमलों के जवाब में ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता को भी रद्द कर दिया है, जबकि क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतें इस घटना के दूरगामी परिणामों पर नजर रख रही हैं। इजरायल ने उत्तरी ईरान के तबरीज पर 10 अलग-अलग ठिकानों पर बमबारी की।

इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले ही हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे और समय आते ही उनसे हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और एयरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजीजादेह समेत कम से कम 20 वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए हैं।

अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रद्द, ट्रंप ने दिया एक और मौका?

तेहरान पर हुए इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से औपचारिक रूप से पीछे हटने की घोषणा कर दी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस तरह के 'आक्रामक और उकसावे वाले कृत्य' के बाद कोई भी बातचीत का आधार नहीं बचता। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के पास अभी भी एक दूसरा मौका है, अगर वे समझौता करना चाहें। हालांकि, इस बयान को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने तनाव को और भड़काने वाला बताया है।

रूस और चीन का क्या है रोल?

इस हमले में ईरान के तीन टॉप लिस्ट सैन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख, रणनीतिक योजना प्रमुख और ईरानी एयर डिफेंस यूनिट के प्रमुख शामिल हैं। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इन तीनों पदों के लिए नए स्थायी नियुक्तियों की घोषणा कर दी है, हालांकि नामों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को लेकर गंभीर चिंता जताई है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। रूस और चीन ने भी इजरायली कार्रवाई की आलोचना करते हुए ईरान के साथ एकजुटता प्रकट की है।

आइए अब 10 सवालों के जवाब में समझें हमले के बारे में सबकुछ...

1. क्या इसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया?

हां, रिपोर्ट्स और तस्वीरों से स्पष्ट है कि तेहरान के कई आवासीय इलाकों और गैर-सैन्य इमारतों को मारा गया ।

2. हमले में कितने नागरिक मारे गए?

अधिकारिक रूप से 78 की मौत और 329 घायल की पुष्टि की गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं ।

3. कौन से परमाणु वैज्ञानिक मरे?

कम से कम छह वैज्ञानिकों की मौत हुई है, जिनमें अब्दुलहामिद मिनोउचेहर, अहमदरेजा जोल्फागरी, सईद अमीरहुसैन फेकी, मोहम्मद मेहदी तेहरांची और फेरेदून अब्बासी शामिल हैं ।

4. क्या अमेरिका को हमलों की जानकारी थी?

हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि उन्हें हमलों की जानकारी थी, और इसी आधार पर अमेरिकी सैन्य टैंकर ईरान के पास तैनात किए गए थे ।

5. क्या अमेरिका इस हमले में शामिल था?

अमेरिका ने सीधे तौर पर सहभागिता की बात नहीं स्वीकारी, लेकिन कई संकेत स्पष्ट हैं-जैसे डिप्लोमैटिक कवरेज, टैंकर स्थिति और इजरायल-अमेरिकी समन्वय ।

6. कौन-से ईरानी सैन्य नेता मारे गए?

रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी, फौज के चीफ-ऑफ-स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और खतम-अल-अनबिया मुख्यालय प्रमुख घोलाम अली रशीद की मौत हो चुकी है।

7. क्या ईरान जवाब देगा?

ईरान ने 'तीव्र, शक्तिशाली' जवाब की बात कही है। अयातुल्ला खामेनेई ने चेताया है कि इजरायल को इसका 'कठोर दंड' भुगतना होगा

8. यह परमाणु वार्ता पर कैसा असर छोड़ता है?

हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही परमाणु बातचीत को रद्द कर दिया है। अमेरिका की तरफ से वार्ता को फिर से शुरू करने की अपील की गई थी ।

9. हमले में इजराइल ने कौन-से हथियार इस्तेमाल किए?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऋ35 स्टील्थ जेट और मिसाइलों के साथ ड्रोन झुंड का इस्तेमाल हुआ ।

10. कई हिस्सों पर हमला हुआ-कहां-कहां निशाना था?

तेहरान के अलावा तबरीज, इस्फहान, हमीदान, अहवाज, खोर्रमाबाद, करमानशाह और कसर-ए-शिरीन जैसे शहर निशाने पर थे ।

क्या इसका मतलब है कि मध्य-पूर्व में एक बड़े युद्ध का रास्ता खुल गया?

एक्सपर्ट्स के अनुसार यह एक 'डिकैपिटेशन' मिशन है-नेतृत्व और क्षमताओं को कमजोर करना मकसद है। अगर ईरान जवाब देता है, तो एक व्यापक संघर्ष भड़क सकता है, खासकर क्योंकि अमेरिका और अन्य देश भी इसमें उलझ सकते हैं। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव चरम पर है ।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

चिनाब पुल ने दिलों को भी जोड़ा है: टी. जी. सीथाराम

नई दिल्ली, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज के निर्माण में प्रारंभ से ही जुड़े रहे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर टी. जी. सीथाराम ने जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली इस पूरी परियोजना को अति विशिष्ट बताते हुए कहा कि चिनाब ब्रिज विश्व का एक नया अजूबा है, जिसका निर्माण भारतीय इंजीनियरों ने किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को हर मौसम में जोड़ने के लिए तैयार किए गए इस पुल ने दिलों को भी जोड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश के हर नागरिक की इसमें जबरदस्त भूमिका है। इंजीनियरिंग की मिसाल इस ब्रिज का सपना साकार करने में हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों ने महती भूमिका अदा की है।

चिनाब ब्रिज के निर्माण की अद्वितीय यात्रा को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि "2005 में जब पहली बार मैंने चिनाब घाटी में कदम रखा, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतिहास के निर्माण का हिस्सा हूँ। वहां की भौगोलिक स्थिति अत्यंत कठिन थी, जमीन अस्थिर थी और अपेक्षाएँ बहुत ऊँची। फिर भी हमारा विजन स्पष्ट था कि हम केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, राष्ट्रीय गौरव का निर्माण करने वाले हैं।"

कश्मीर की पर्याय चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल को "विज्ञान, आत्मा और राष्ट्रीय चेतना की यात्रा" बताते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों की इस प्रक्रिया में हजारों इंजीनियरों, श्रमिकों और वैज्ञानिकों का समर्पण समाहित है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (क्क्रू) की टीम के साथ पुल के निर्माण में अपनाए गए लचीले दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला, जिसमें रीयल टाइम फील्ड डेटा, एडवांस सिमुलेशन और समावेशी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल शामिल था, ताकि भौगोलिक अस्थिरता और दुर्गम इलाकों की चुनौती पर फतह हासिल की जा सके।

प्रो. सीथाराम ने कहा कि "हर कील, हर नींव और सपोर्ट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि विश्वास का निर्माण था। इंजीनियरिंग सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। चिनाब ब्रिज इस बात का जीवंत प्रमाण है कि समर्पण, विज्ञान और राष्ट्र के प्रति प्रेम से असंभव भी संभव बन जाता है। अगर हम चिनाब पर पुल बना सकते हैं तो युवा भारत किसी भी ऊंचाई को छू सकता है।"

पश्चिम रेलवे का रविवार, 15 जून, 2025 को सांताक्रुज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच जंबो ब्लॉक

मुंबई, 13 जून, 2025

रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रखरखाव कार्य हेतु रविवार, 15 जून, 2025 को सांताक्रुज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच तक अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर 10:00 बजे से 15:00 बजे तक पांच घंटे का जंबो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान सांताक्रुज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच स्लो लाइन की सभी ट्रेनों को फास्ट लाइनों पर चलाया जाएगा। परिणामस्वरूप, ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण विले पार्ले स्टेशन पर नहीं रुकेंगी और फास्ट लाइनों पर प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण राम मंदिर स्टेशन पर भी नहीं रुकेंगी। हालाँकि, हार्बर लाइन पर विले पार्ले और राम मंदिर के लिए सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी।

इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा बोरीवली और अंधेरी की कुछ ट्रेनें हार्बर लाइन पर गोरेगांव तक चलेंगी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के कार्यालय में उपलब्ध है।

विमान दुर्घटना के बाद अहमदाबाद रेल मण्डल ने की त्वरित कार्यवाही

अहमदाबाद में हुई दुखद विमान दुर्घटना के बाद पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल द्वारा तत्काल राहत और बचाव कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (फ्ध्क्र) टीम एवं एम्बुलेंस सहित मेडिकल टीम को बचाव और राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के भेजा गया।

12 जून, 2025 को 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद अहमदाबाद के मेघाणी नगर में बी.जे. मेडिकल कॉलेज छात्रावास के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोपहर 14:20 बजे समाचार मिलने पर आरपीएफ ने 12 सदस्यीय आपदा प्रबंधन टीम और एम्बुलेंस के साथ त्वरित कार्रवाई की, एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल स्टाफ सहित रेलवे अस्पताल की मेडिकल टीम ने घायल व्यक्तियों की मदद की। आरपीएफ को सूचना मिलते ही वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्रीमती भवप्रीता सोनी के निर्देश पर सहायक सुरक्षा आयुक्त लाइन, श्री संजय चौधरी, आईपीएफ श्री मनु छोकर असारवा तथा अन्य रेलवे सुरक्षा बल कर्मी तुरंत दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

फ्ध्क्र टीम फर्स्ट रेसपोंस में शामिल रही, टीम ने राज्य एजेंसियों जैसे रउफ्क्ष्ठ सिविल डिफेंस तथा केंद्रीय एजेंसियों जैसे उक्रत्क्ष्ठ ठरञ्क्ष् और मेडिकल टीमों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया उन्होंने मृतकों को एंबुलेंस तक पहुंचाने में भी मदद की।

श्रीमती भवप्रीता सोनी वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त एवं श्री अन्नू त्यागी वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरी टीम को जरूरी मार्गदर्शन दिया विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया।

14 जून से गांधीधाम-जोधपुर एक्सप्रेस में 6 कोचों की बढ़ोतरी

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 22484/22483 गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 6 अतिरिक्त कोचों की बढ़ोतरी की जा रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 22484/22483 गांधीधाम-जोधपुर-गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 14 जून 2025 से गांधीधाम से तथा 13 जून 2025 से जोधपुर से एक एसी-2 टियर, एक एसी-3 टियर, दो एसी-3 टियर इकोनोमी और दो स्लीपर श्रेणी सहित कुल 6 कोचों की बढ़ोतरी की जा रही है।

ट्रेनों के ठहराव के समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया

इस सम्मेलन में शैक्षिक उत्कृष्टता, क्षेत्रीय प्रासंगिक अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता, साक्ष्य-आधारित और किफायती स्वास्थ्य सेवा को पुनर्परिभाषित करने तथा अंत:विषय सहयोग को बढ़ावा देने में सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया

यह सम्मेलन शिक्षण-अधिगम और अनुसंधान; अस्पताल सेवाएं; तथा शासन और रोगी सुविधा के क्षेत्रों में नए एम्स के समृद्ध अनुभवों को समेकित करने की एक अग्रणी पहल है : श्री नड्डा

"एम्स परिसर उन्नत बुनियादी ढांचे और विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उच्च गुणवत्ता, साक्ष्य-आधारित और किफायती उपचार प्रदान करके रोगी देखभाल को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं"

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न एम्स संस्थानों द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय विधियों को दशार्ना है, जिसमें रोगी-केंद्रित देखभाल, परिचालन दक्षता, डिजिटल परिवर्तन और अकादमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश भर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स भोपाल, एम्स जम्मू, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स देवघर, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स रायपुर) के साथ-साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) प्रभाग और रक्षा मंत्रालय ने सम्मेलन में सहयोग किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया।

श्री नड्डा ने अपने संबोधन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित प्रत्येक एम्स उन्नत नैदानिक देखभाल, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान उत्कृष्टता को एकीकृत करता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित प्रत्येक एम्स स्वास्थ्य सेवा नवाचार और सीखने के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो समान, किफायती और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ये संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, देखभाल के मानकों को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा जुड़े विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी को विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।"

श्री नड्डा ने प्रत्येक नए एम्स की सर्वोत्तम विधियों और नवाचारों को अन्य एम्स के साथ साझा करने के महत्व पर जोर दिया ताकि उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। उन्होंने एम्स नागपुर की ह्वअग्रणी भूमिका निभाने और सर्वोत्तम विधियों पर पहला सम्मेलन आयोजित करनेह्व के लिए भी सराहना की।

श्री नड्डा ने सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सम्मेलन शिक्षण-अधिगम और अनुसंधान; अस्पताल सेवाएं; तथा शासन और रोगी सुविधा के क्षेत्रों में नए एम्स के समृद्ध अनुभवों को समेकित करने की एक अग्रणी पहल है।

श्री नड्डा ने भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए डॉक्टरों को तैयार करने में एम्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि 'शिक्षण-अध्ययन के क्षेत्र में, योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम को अपनाना, डिजिटल शिक्षण में निवेश, अत्याधुनिक सिमुलेशन प्रयोगशालाएं और संरचित मेंटरशिप कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है।'

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि "नए एम्स क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक अध्ययनों, नैतिक नैदानिक परीक्षणों और अनुवाद संबंधी शोध के माध्यम से देश की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास आने वाले वर्षों में जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने की मदद करेंगे।"

श्री नड्डा ने कहा, "एम्स परिसर उन्नत बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले, साक्ष्य-आधारित और किफायती उपचार प्रदान करके रोगी देखभाल को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। ई-गवर्नेंस टूल, पारदर्शी प्रशासनिक ढांचे और जन औषधि केंद्र, डिजिटल पंजीकरण प्रणाली और समर्पित हेल्पडेस्क जैसे रोगी-केंद्रित नवाचारों का उपयोग यह दशार्ता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में दक्षता और करुणा एक साथ शामिल हो सकती है।"

अपने संबोधन में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने ह्वचिकित्सा शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टताह्व के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्थागत विकास नेतृत्व के दृष्टिकोण ने अन्य संस्थानों की सर्वोत्तम विधियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (पीएमएसएसवाई) श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला, एम्स नागपुर की कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रशांत पी. जोशी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (रक्षा मंत्रालय) के महानिदेशक, सीआईआरए (रक्षा मंत्रालय), देश भर के विभिन्न एम्स के कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ प्रशासक भी शामिल हुए।

माईगॉव ने मंत्रालयों और विभागों में डिजिटल शासन संचार मजबूत करने के लिए "Think Socal @ MyGov" कार्यशाला का आयोजन किया

माईगॉव ने मंत्रालयों और विभागों में डिजिटल शासन संचार मजबूत करने के लिए "Think Socal @ MyGov" कार्यशाला का आयोजन किया

कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों के डिजिटल संचार पेशेवरों के साथ ही यूट्यूब और मेटा विशेषज्ञों ने भाग लिया

माईगॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नंद कुमारम ने नागरिक-केंद्रित शासन आगे बढ़ाने में इसके बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत माईगॉव ने 12 जून 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक दिवसीय कार्यशाला "Think Social @ MyGov" का आयोजन किया। कार्यशाला में मंत्रालयों और विभागों में डिजिटल संचार मजबूत करने और यूट्यूब, मेटा और लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्म द्वारा नागरिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह पहल समावेशी संचार द्वारा जनभागीदारी के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा माईगॉव के मुख्य कार्यकारी श्री नंद कुमारम तथा माईगॉव के निदेशक श्री शोभेन्द्र बहादुर, और माईगॉव के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ।

श्री नंद कुमारम ने अपने संबोधन में माईगॉव की डिजिटल यात्रा का उल्लेख करते हुए नागरिक-केंद्रित शासन को आगे बढ़ाने में इस मंच के बढ़ते प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने युवाओं से जुड़ने और शासन संचार मजबूत करने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रेखांकित की। उन्होंने प्रमुख अभियानों का उल्लेख किया जिनसे व्यापक स्तर पर सार्वजनिक भागीदारी हुई और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। श्री नंद कुमारम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनभागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप प्रभावी नीति-निर्माण और समावेशी जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगे और अधिक लाभकारी योजना की भी रूप-रेखा रखी।

श्री शोभेन्द्र बहादुर ने माईगॉव की 11 वर्ष की यात्रा तथा प्रमुख सरकारी अभियानों और नागरिक भागीदारी में इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।

कार्यशाला में मंत्रालयों और विभागों में डिजिटल संचार बढ़ाने और यूट्यूब और मेटा जैसे प्लेटफार्म द्वारा नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के डिजिटल संचार पेशेवरों ने भाग लिया। यूट्यूब और मेटा के विषय विशेषज्ञों ने वरिष्ठ माई गॉव अधिकारियों के साथ मिलकर ज्ञान सत्र आयोजित किए। इनमें आवश्यक सामग्री विकसित करने, प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस और दर्शक सहभागिता पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यशाला में सोशल मीडिया के निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया गया:

दृश्यता, सहभागिता और पहुंच में सुधार लाना

गूगल ट्रेंड्स जैसे विश्लेषण उपकरणों का इस्तेमाल

रील्स और स्टोरीज जैसे दृश्य सामग्री प्रारूप

दर्शकों के व्यवहार और लक्षित विषय-वस्तु की समझ

व्हाट्सएप एपीआई, थ्रेड्स और मेटा एआई पर चर्चा

इसके अलावा, विषय से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार की प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर ज्ञान साझा किए:

सुश्री गरिमा तिवारी ने माईगॉव की प्रमुख पहल, प्रमुख उपलब्धियों और परिलक्षित परिणामों को जानने पर प्रस्तुति दी।

श्री आशीष खरे ने विशिष्ट सामग्री निर्माण, बहु-प्लेटफॉर्म वितरण ढांचे और सरकार के संदेशों को डिजिटल लोकप्रिय स्वरूप में पहुंचाने पर सत्र को संबोधित किया।

श्री उपेन्द्र उपाध्याय ने डिजिटल अभियानों में सूचित निर्णय लेने और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स के लाभ उठाने की जानकारी दी।

श्रीमती रेणु सिंह ने महत्वपूर्ण रूप से लोगों तक संदेश पहुंचाने, अंतर-एजेंसी साझेदारी और उच्च प्रभाव वाले राष्ट्रीय अभियानों के मामले के विस्तृत गहन अध्ययन का उल्लेख किया।

कार्यशाला के दौरान कई अभियानों और महत्वपूर्ण, विशिष्ट मामलों को रेखांकित किया गया:

परीक्षा पे चर्चा 2025 झ इसमें अभूतपूर्व रूप से 3 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता हुई जिससे सहभागी शासन को मजबूती मिली।

राष्ट्रीय सृजन पुरस्कार झ इसमें डेढ़ लाख नामांकन दर्ज किए गए और 6,000 लोगों की व्यापक सामुदायिक भागीदारी रही।

चंद्रयान तीन महा प्रश्नोत्तरी झ इस राष्ट्रीय ज्ञान अभियान में शीर्ष 100 विजेताओं के लिए श्रीहरिकोटा की अनुभवात्मक यात्रा हुई।

कैम्पस एम्बेसडर कार्यक्रम - संरचित शैक्षणिक सहभागिता द्वारा युवाओं को शासन में सक्रिय पक्षधर के रूप में सशक्त बनाना।

जीडीपी पॉडकास्ट और रोअर फॉर नेचर - नीति, जलवायु और स्थिरता विषयों पर युवाओं को जागरुक और प्रेरित करने की महत्वपूर्ण पहल रही।

कोविड-19 के दौरान माईगॉव व्हाट्सएप सेवाएं - नागरिकों को टीकाकरण प्रमाणपत्रों और सत्यापित अपडेट की निर्बाध पहुंच प्रदान की गई।

ऑपरेशन सिंदूर - फर्जी और भ्रामक खबरों से निपटने और सत्यापित सरकारी सूचनाओं के वास्तविक समय पर प्रसार को सक्षम बनाने के मामले का अध्ययन।

माईगॉव स्ट्रीम - नागरिक-केंद्रित, शासन-संबंधी सामग्री तैयार करने हेतु समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरूआत।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विषय-वस्तु की निरंतरता, कथ्य आधारित संचार और दर्शकों की प्रासंगिकता पर जोर।

पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभाव मापन को समुन्नत बनाने के लिए डेटा-संचालित संचार मॉडल अपनाना।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर सहित कई गाड़ियों का हुआ अस्थाई रूप से मार्ग विस्तार

(जीएनएस)।

रेलवे प्रषासन द्वारा आधारभूत संरचना में विस्तार एवं यात्री सुविधाओं में उन्नयन हेतु गोरखपुर स्थित ओल्ड पिट लाइन संख्या-1 एवं 2 के पुनर्निर्माण के परिप्रेक्ष्य में डिस्मेंटल कार्य हेतु ब्लाक दिये जाने के कारण निम्नलिखित गाड़ियों का अस्थाई रूप से मार्ग विस्तार किया गया था। इन गाड़ियों के कुछ स्टेषनों के समय में निम्नवत परिवर्तन किया गया है।

- 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर वाया मऊ गोदान एक्सप्रेस 16 जून से 07 दिसम्बर, 2025 तक प्रत्येक

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 10.55 बजे प्रस्थान कर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते

हुये दूसरे दिन संषोधित समयानुसार गोरखपुर से 20.45 बजे तथा बस्ती से 21.47 बजे छूटकर विस्तारित मार्ग गोण्डा स्टेषन पर

23.05 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाया मऊ गोदान एक्सप्रेस 18 जून से 07

दिसम्बर,2025 तक प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को विस्तारित मार्ग गोण्डा स्टेषन से 03.10 बजे प्रस्थान कर

बस्ती से 04.18 बजे तथा गोरखपुर से 06.40 बजे छूटकर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते हुये दूसरे दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस

15.30 बजे पहुंचेगी।

- 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर वाया ऐषबाग, गोण्डा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 जून से 05 दिसम्बर,2025

तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 05.23 बजे प्रस्थान कर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते हुये दूसरे दिन गोरखपुर 12.05 बजे,

देवरिया सदर से 12.55 बजे, भटनी से 13.14 बजे तथा मऊ से 14.12 बजे छूटकर विस्तारित मार्ग आजमगढ़ 15.15 बजे पहुंचेगी।

वापसी यात्रा में 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाया गोण्डा, ऐषबाग सुपरफास्ट एक्सप्रेस 17 जून से 06

दिसम्बर,2025 तक विस्तारित मार्ग आजमगढ़ से 18.50 बजे प्रस्थान कर मऊ से 19.30 बजे, संषोधित समयानुसार भटनी से

20.54 बजे, देवरिया सदर से 21.16 बजे, गोरखपुर 22.10 बजे छूटकर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते हुये तीसरे दिन लोकमान्य

तिलक टर्मिनस 04.35 बजे पहुंचेगी।

- 19409 साबरमती-गोरखपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस 19 जून से 06 दिसम्बर,2025 तक प्रत्येक वृहस्पतिवार एवं शनिवार

को साबरमती से 10.35 बजे प्रस्थान कर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते हुये दूसरे दिन गोरखपुर से 17.00 बजे, विस्तारित मार्ग पर

कप्तानगंज से 18.07 बजे, पड़रौना से 18.44 बजे तथा तमकुही रोड से 19.22 बजे छूटकर विस्तारित मार्ग थावे 20.30 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 19410 गोरखपुर-साबरमती द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस 21 जून से 08 दिसम्बर,2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को विस्तारित मार्ग थावे से 01.00 बजे प्रस्थान कर तमकुहीरोड से 01.45 बजे, पड़रौना से 02.32 बजे, कप्तानगंज से 03.32 बजे तथा गोरखपुर से 04.55 बजे छूटकर पूर्व निर्धारित स्टेषनों पर रूकते हुये दूसरे दिन साबरमती 09.55 बजे पहुंचेगी।

एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन: डेटा की डिलीवरी में तब्दीली

कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी ने पारदर्शी, किसान केंद्रित गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया

(जीएनएस)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में "एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन: डेटा की डिलीवरी में तब्दीली" का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक रणनीतिक मंच का काम किया।

हँ३२अस्रस्र वेंौ 2025-06-13 ं३ 7.38.33 ढद्व.स्रीं

इस सम्मेलन की शुरूआत कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने पारदर्शी, किसान-केंद्रित गवर्नेंस हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जोर दिया कि राज्यों द्वारा अपडेटेड अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) के साथ अपनी किसान रजिस्ट्री को गतिशील ढंग से जोड़ने की और योजना वितरण तथा व्यक्तिगत कृषि सेवाओं के लिए डिजिटल डेटासेट का सक्रिय रूप से उपयोग करने की तत्काल जरूरत है। भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने अपने मुख्य भाषण में सटीक किसान पहचान के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और आधार सीडिंग की बुनियादी भूमिका पर बल दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मूल्य और आय में गिरावट की चुनौतियों का जिक्र किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के

अतिरिक्त सचिव (डिजिटल) श्री प्रमोद कुमार मेहरदा ने एग्री स्टैक के बारे में व्यापक रूप से बताया जिसमें पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, केसीसी जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ किसान आईडी का एकीकरण शामिल है। उन्होंने जियोरेफरेंसिंग, डेटा गुणवत्ता के आश्वासन और एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई) मानकों के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। इस सम्मेलन में किसान प्राधिकरण प्रणाली और डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र (डीवीसी) जैसी आगामी सेवाओं की शुरूआत भी हुई, जिससे किसानों को अपनी भूमि और फसल की जानकारी सुरक्षित और चयनित रूप से साझा करने का अधिकार मिला।

हँ३२अस्रस्र वेंौ 2025-06-13 ं३ 7.38.32 ढद्व.स्रीं

इस दिन एक प्रमुख उपलब्धि महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का गठबंधन रहा। यह गठजोड़ किसान रजिस्ट्री से जुड़े प्रमाणीकरण के जरिए ऋण सेवाओं तक बेरोक डिजिटल पहुंच को सक्षम करेगा, कागजी कार्रवाई को कम करेगा और पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा, अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कृषि और भूमि संसाधन सचिवों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और सलाहकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा संयुक्त रूप से विशेष केंद्रीय सहायता दिशा-निर्देश जारी किए गए। राज्यों को समर्थन देने के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई। इनमें किसान रजिस्ट्री (कानूनी उत्तराधिकारी प्रणाली सहित) के लिए 4,000 करोड़ रुपये और पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। मुख्य ज्ञान अधिकारी और सलाहकार के नेतृत्व में हुए तकनीकी सत्रों में राज्य स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, डेटा की गुणवत्ता में फर्क को दूर करने और डीसीएस मानकों के अनुपालन को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सटीकता और दक्षता को बेहतर करने के लिए रिमोट सेंसिंग, एआई/एमएल उपकरण और स्वचालित डेटा सत्यापन तंत्र का उपयोग करने पर जोर दिया गया।

एग्री स्टैक के उपयोग पर राज्यों की जानकारियां शीर्षक वाले एक समर्पित सत्र में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की प्रस्तुतियां शामिल थीं। महाराष्ट्र ने अपने राज्य में किसानों की रजिस्ट्री में किसानों के नामांकन और एससीए माइलस्टोन को छूने में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया। उसने डेटा प्रोविजनिंग इंजन (डीपीई) की स्थापना, महाडीबीटी में किसान आईडी आधारित नामांकन को सक्षम करने और एआई आधारित सलाह (महाविस्तार एआई) के लिए एक अभिनव सैंडबॉक्स के निर्माण के लिए केंद्र से समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश ने 2024 के लिए एमएसपी ई-खरीद के साथ एग्री स्टैक को एकीकृत करने के अपने इस्तेमाल के बारे में बताया और डीसीएस कार्यान्वयन में क्षेत्र की चुनौतियों को साझा किया।

अहमदाबाद विमान हादसा : राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत-बचाव और चिकित्सा सेवा कार्यों के जरिए आपदा प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया

गांधीनगर, 13 जून : अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एअर इंडिया विमान के दर्दनाक हादसे में राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया था।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को इस हादसे की जानकारी मिलते ही, उन्होंने तत्काल समूचे प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में शामिल होने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसियों की मदद भेजी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद आकर दुर्घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात भी की, साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को राहत और बचाव कार्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया।

विमान दुर्घटनास्थल पर सेना के 250 से अधिक जवानों, रैपिड एक्शन फोर्स की 1 टीम, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 3 टीमों ने राहत और बचाव कार्यों के लिए मोर्चा संभाला।

केवल 3 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में दमकल (फायर सर्विसेज) की दो टीमों ने घटना स्थल पर पहुंचकर 30 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। दमकल विभाग के 612 कर्मचारियों ने 139 विभिन्न फायर उपकरणों के साथ विमान के मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने और आसपास के क्षेत्र में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए पहुंचाने में सहायता की। पुलिस विभाग ने घटना स्थल पर शवों और मानव अंगों को तलाशने के लिए विशेष डॉग स्क्वॉड को भी काम पर लगाया।

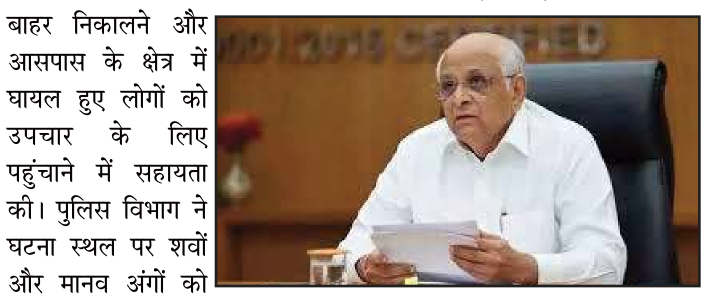

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान 100 से अधिक एंबुलेंस की सेवाएं ली गईं।

घायलों के उपचार के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल टीमें तैनात थीं और स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल के सीधे मार्गदर्शन में घायलों का उपचार शुरू किया गया।

राज्य सरकार ने इस हादसे की अत्यंत संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल में प्रभावितों-घायलों के परिजनों के मार्गदर्शन के लिए 4 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। एसईओसी में 16 उप कलेक्टर और 16 तहसीलदार की टीम कार्यरत की गई है।

इसके अलावा, विमान यात्रियों के रिश्तेदारों को उचित जानकारी और मदद के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और सिविल हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक- 247 कंट्रोल रूम संचालित किया गया है। राज्य सरकार के सड़क और भवन विभाग द्वारा इस हादसे के शिकार बने यात्रियों के परिजनों के लिए अहमदाबाद में ठहरने और वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

दुर्घटनास्थल के आसपास के रिहायशी इलाकों में हादसे का शिकार बने लोगों में से आठ व्यक्तियों के शवों की शिनाख्त होने पर उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

विमान हादसे का शिकार बने व्यक्तियों के लगभग 219 परिजन अब तक डीएनए टेस्टिंग और ब्लड सैंपल के लिए पहुंच चुके हैं, उनके सैंपल ले लिए गए हैं, जबकि बाकी बचे परिजनों का इसके लिए संपर्क किया गया है। इसके लिए एफएसएल की 10 टीमों के लगभग 36 विशेषज्ञ 247 कार्यरत हैं।

इस हादसे के बाद लगभग 50 लोगों को घायल अवस्था में सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। इन घायलों में से 16 को आउटडोर पेशेंट के रूप में तथा 31 को इंडोर पेशेंट के रूप में उपचार दिया जा रहा है। आज शाम तक 12 घायलों को छुट्टी दे दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को विभिन्न जिलों और शहरों में रहने वाले यात्रियों के परिवारों से संपर्क करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने स्वयं चलकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और परिजनों को सांत्वनाएं देने का साथ आवश्यक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, विशेष टीमों का गठन कर इस हादसे का शिकार बने यात्रियों के परिजनों की काउंसलिंग कर उन्हें मार्गदर्शन और मनोबल प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने दुर्घटनास्थल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ कामकाज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सड़क एवं भवन विभाग के लगभग 150 कर्मचारियों, 41 डम्पर-ट्रैक्टर, 16 जेसीबी और 3 एक्सकेवेटर को स्टैंडबाय पर रखा है।

इस प्रकार, स्वास्थ्य, एफएसएल, दमकल, पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के उच्च सचिवों के सुचारू समन्वय से हुए कार्यों ने राज्य की आपदा प्रबंधन की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है।

मुलायम सिंह के करीबी और कन्नौज के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन, अखिलेश यादव ने जताया दुख

,,

पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने कन्नौज सीट से साल 1980, 1989 और 1991 में जीत दर्ज की थी. कुछ दिनों पहले ही कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर छोटे सिंह यादव से मुलाकात की थी. मुलायम सिंह के करीबी और कन्नौज के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन, अखिलेश यादव ने जताया दुख , समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक सदस्य एवं कन्नौज लोकसभा सीट से तीन बार के सांसद रहे छोटे सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. छोटे सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

सपा प्रमुख यादव ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ॠसहकारिता आंदोलन के पुरोधा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कन्नौज से कई बार सांसद एवं छिबरामऊ से विधायक रहे श्री छोटे सिंह यादव जी का निधन, अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.ॠ यादव ने कहा, ॠशोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि !ॠ

कन्नौज लोकसभा सीट से तीन बार रहे सांसद

पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर वर्ष 1980, 1989 और 1991 में जीत दर्ज की थी. कुछ दिनों पहले ही कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर छोटे सिंह यादव से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली थी. छोटे सिंह यादव के निधन से सपा कार्यकर्ता भी काफी दुखी हैं.

छिबरामऊ से विधायक भी रहे थे छोटे सिंह यादव

छोटे सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वह सहकारिता आंदोलन में योगदान के लिए जाने जाते थे. छोटे सिंह यादव कन्नौज से सांसद के अलावा छिबरामऊ से विधायक भी रहे थे. छोटे सिंह यादव का जन्म कन्नौज जिले के एक सामान्य परिवार में हुआ था और वह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में शामिल हो गए थे. छोटे सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव का काफी करीबी माना जाता था.

कोईनसाला आईपीओ घोटाला, सायबर क्राइम भोपाल ने जोधपुर से तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को किया गिरफ्तार

(जीएनएस)।

भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के जोधपुर से तीन ऐसे अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 'कोईनसाला मीडिया प्रा. लि. ' नामक एक फर्जी क्रिप्टो कंपनी के नाम पर भोपाल निवासी एक युवक से 18.60 लाख रुपये की ठगी कर चुके थे।

गिरफ्तार आरोपियों में नरेंद्र (21), निम्बाराम (22) और चंदन मांझी (37) शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनुराग शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त शैलेंद्र चौहान और सहायक पुलिस आयुक्त साइबर सुजीत तिवारी के मार्गदर्शन में हुई।

कैसे फंसा जाल में फरियादी

यह मामला तब सामने आया जब भोपाल के अवधपुरी निवासी सुधीर सिंह (38) ने 20 अक्टूबर 2024 को सायबर क्राइम, कोहेफिजा में शिकायत दर्ज की। सुधीर ने बताया कि सितंबर 2024 में वह टेलीग्राम के जरिए कोईनसाला मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़े, जो क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन का दावा करती थी। शुरूआत में सुधीर ने 2,000, 5,000, और 8,000 रुपये का निवेश किया, जिसके बदले उन्हें कुछ ही दिनों में 20,000 रुपये का रिटर्न मिला। यह रिटर्न देखकर उनका भरोसा बढ़ा और वे कंपनी के जाल में फंसते चले गए।

आरोपियों ने सुधीर को टेलीग्राम पर एक विशेष ग्रुप में जोड़ा, जहां निवेश से जुड़ी गतिविधियां करवाई जाती थीं। इन गतिविधियों में 5,000, 30,000, और 1,20,000 रुपये का निवेश करने के बाद, जब सुधीर ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उन्हें 3.60 लाख रुपये की एक और "एक्टिविटी" में हिस्सा लेने को कहा गया। इधर-उधर से पैसे जुटाकर सुधीर ने यह राशि भी निवेश कर दी। लेकिन जब दोबारा निकासी की कोशिश की, तो 6.80 लाख रुपये की एक और एक्टिविटी में निवेश की मांग की गई।

कंपनी का ऐप डैशबोर्ड सुधीर को भारी रिटर्न दिखा रहा था, जिससे उनका भरोसा और पक्का हो गया। इस तरह विभिन्न किस्तों में कुल 18.60 लाख रुपये की ठगी की गई। शिकायत के बाद 8 फरवरी 2025 को धारा 318(4) और 319(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

आरोपियों का तरीका, कॉलेज स्टूडेंट्स को बनाया निशाना

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नरेंद्र ने अपने भाई के बंद हो चुके बंधन बैंक खाते को 10,000 रुपये में निम्बाराम को बेचा।

मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 34वीं रिपोर्ट जारी

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 34वीं रिपोर्ट जारी की

मई 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लोक शिकायत के कुल 67,787 मामले प्राप्त हुए और 78,123 शिकायतों का निवारण किया गया

सेवोत्तम योजना के तहत 855 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं, जिनमें 28,438 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

मई 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 78,123 शिकायतों का निवारण किया गया। मई 2025 के महीने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 1,97,787 है। फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 में कुल 65,601 फीडबैक एकत्र किए, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 26,633 फीडबैक एकत्र किए गए।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण का आयोजन	अधिकारियों का प्रशिक्षण
1	2022-23	280	8.496
2	2023-24	236	8.477
3	2024-25	306	10.257
4	2025-26	33	1.208
कुल		855	28,438

रिपोर्ट मई 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकताओं के लिए डेटा प्रदान करती है। मई 2025 के महीने में कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (10,043 पंजीकरण) से हुए।

उक्त रिपोर्ट मई 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। मई 2025 के महीने में सीएससी के माध्यम से 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं। यह उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डालती है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

मई 2025 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 26,634 थी। 31 मई, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने मई 2025 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 26,658 और 14,369 थी। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 31 मई , 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है ।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26) में 855 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें 28,438 से भी ज्यादा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मई 2025 माह के लिए मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

मई, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोक शिकायत के 67,787 मामले (पीजी) प्राप्त हुए और 78,123 पीजी मामलों का निवारण किया गया।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक निपटान अप्रैल, 2025 के अंत में 57,021 पीजी मामलों से बढ़कर मई, 2025 के अंत में 78,123 पीजी मामले हो गए।

सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

31 मई, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।

31 मई, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,97,787 पीजी मामले लंबित हैं।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव

16 जून 2025 से शुरू होकर, छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्कूल नामांकन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर जोर देते हैं।

इ८ डल्लीर्ल्ल्र्ी र३ा

व्ळी ढ४ु'रौंः ऋ८ि, ख४ल्ली 13, 2025, 19:02 [क्रळ]

ऋङ्क्ष्ट्री डल्लीर्ल्ल्र्ी ठी६२

छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून 2025 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर "शाला प्रवेश उत्सव" में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

उँ३३र१ँ छं४ल्ल्ौ२ रूँङ्क्ष' ओ२ि२ङ्गल्ल त्री२३५'

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि "असंभव को संभव" बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और सभी बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे-धीरे शून्य किया जाए। इसके लिए शैक्षणिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी सभी हितधारकों की साझा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान" की शुरूआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना है। इसके साथ ही, सरकार द्वारा शिक्षकों एवं विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्राथमिकता से पदस्थापना की गई है, जिससे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के विकास को सरकार ने अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे शाला प्रवेश उत्सव के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहभागिता करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे।

सामाजिक सहभागिता से संवरता भविष्य

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे" इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर परिणाममूलक कार्य करने होंगे। उन्होंने आशा जताई कि सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान का नेतृत्व कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शाला प्रवेश उत्सव को बनाएं जनअभियान

मुख्यमंत्री के इस पत्र को राज्य में शिक्षा को लेकर एक जनांदोलन की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल बच्चों की स्कूल तक पहुंच बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक सहभागिता को भी एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

इस 'फादर्स डे' पर पिता को दें ये खास गिफ्ट, पापा भावुक होकर लगा लेंगे आपको गले

(जीएनएस)।

'पिता' एक ऐसा शब्द है जिसमें ताकत है, त्याग है, सख्ती भी और सबसे ज्यादा केयर है । जब हम छोटे थे, तो उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। जब गिरे, तो उन्होंने बिना जताए संभाल लिया। उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारे लिए रास्ते बनाया।

15 जून 2025 को मनाया जाएगा फादर्स डे

इस बार 15 जून 2025 (रविवार) को फादर्स डे मनाया जाएगा। इस खास मौके पर आप अपने पिता को खुश करने के लिए उनके साथ समय बिताएं और साथ ही उन्हें कुछ खास गिफ्ट भी दें। दरअसल पिता के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उनका महत्व समझना और उन्हें महसूस कराना है कि आप उनके त्याग को पहचानते हैं।

पापा को आपकी मौजूदगी और आभार दीजिए

पिता हमारे लिए वो पेड़ होते हैं जो हमें धूप से बचाते हैं, लेकिन अपनी छांव की अहमियत कभी नहीं जताते। इस फादर्स डे पर उन्हें सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी, आपका समय और आपका आभार दीजिए।

फादर्स डे पर पापा को दें अपना पूरा समय

इस बार फादर्स डे को सिर्फ एक औपचारिकता न बनाएं, बल्कि एक ऐसा मौका बनाएं, जिसमें आप अपने पापा को वो सब दे सकें, जो उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं होगा पर हमेशा चाहा होगा। क्योंकि असली तोहफा वो नहीं होता जो डिब्बे में हो, असली तोहफा वो होता है जो दिल से दिया जाए।

फादर्स डे पर पापा को दें ये खास गिफ्ट्स

एक हैंडमेड लेटर या नोटबुक

भले ही आपने अपने पापा से कभी कुछ न कहा हो, लेकिन इस बार अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिखिए। उनके संघर्ष, उनकी मुस्कान और उनके खामोश प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। एक-एक शब्द उन्हें भीतर तक छू जाएगा।

उनका पसंदीदा वक्त

फादर्स डे पर पापा के साथ एक पूरा दिन बिताएं। इस दिन फोन को छोड़ दें, ऑफिस के बारे में न सोचें। पापा के साथ बैठें, पुराने एल्बम निकालें, उनकी पसंदीदा फिल्म देखें या शाम को छत पर साथ बैठकर चाय पीएं। आपको देखकर उनके चेहरे की जो चमक होगी, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा।

हेल्थ से जुड़ा तोहफा

पापा अक्सर खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें कोई फिटनेस बैंड, रेगुलर हेल्थ चेकअप का प्लान या एक बढ़िया मसाज चेयर गिफ्ट कर सकते हैं। ये तोहफा न सिर्फ उनकी सेहत का ख्याल रखेगा, बल्कि उन्हें ये भी महसूस कराएगा कि अब आप उनका ख्याल रखने लगे हैं।

पापा का अधूरा सपना पूरा करने की कोशिश

क्या आपके पापा ने कभी कहा था कि वह पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना चाहते थे या कोई किताब लिखना चाहते थे? इस फादर्स डे, उनके उस अधूरे सपने की ओर एक कदम बढ़ाइए। साथ खड़े होकर कहिए- अब आपकी बारी है पापा।

रक्षा सचिव ने नोमैडिक एलीफेंट नामक भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के समापन समारोह में भाग लिया

(जीएनएस)।

नोमैडिक एलिफेंट नामक 17वां भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आज मंगोलिया के उलानबटार में संपन्न हुआ। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक एवं स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह समापन समारोह में शामिल हुए।

भारतीय सेना की टुकड़ी ने दो सप्ताह तक चले अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से अरुणाचल स्काउट्स की एक बटालियन के 45 कर्मी शामिल थे। संयुक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में अर्ध-पारंपरिक परिदृश्यों में एक संयुक्त कार्य बल के रूप में काम करते हुए भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच संचालन को परस्पर बढ़ाना था।

समापन समारोह में अपने संबोधन में रक्षा सचिव ने नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास के दौरान भारतीय सैनिकों के पेशेवर कौशल, समर्पण और आचरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच मैत्री, आपसी विश्वास और साझा सांस्कृतिक संबंधों के स्थायी बंधन का प्रमाण है। इसने सार्थक सैन्य सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम किया और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की संयुक्त पहलों में भारतीय सेना का योगदान न केवल संचालन संबंधी तत्परता को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक शांति के प्रयासों में एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में भारत की भूमिका को भी मजबूत करता है।

रक्षा सचिव कल उसी स्थान पर बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भी भाग लेगी। 14 से 28 जून, 2025 तक अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 आयोजित किया जाएगा।

नोमैडिक एलीफेंट और खान क्वेस्ट अभ्यासों का आयोजन भारत की विस्तारित रक्षा संबंधी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मंगोलिया के साथ इसकी साझेदारी के रणनीतिक महत्व को दशार्ता है।